www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 326 | जौनपुर शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

आत्मनिर्भर भारत का बड़ा मील का पत्थर - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। वे जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा दिन है। जींद पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, आज भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा दिन है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने संस्कृत सुभाषितम्श भी शेयर किया, जिसमें लिखा, ष्प्रभूतं कार्यमल्पं वा यन्नरः कर्तुमिच्छति। सर्वारम्भेण तत् कार्यं सिंहादेकं प्रचक्षते।ष इसका अर्थ है, ष्चाहे कार्य बहुत बड़ा हो या छोटा–जिसे मनुष्य करना चाहता है, उसे पूर्ण समर्पण और नए उत्साह के साथ करना चाहिए, यही एक गुण सिंह से सीखने योग्य है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भारत में ही डिजाइन, इंजीनियरिंग और एकीकृत की गई है। यह ट्रेन स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसके साथ ही, भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइड्रोजन–चालित ट्रेनें परिचालन में हैं। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में सिर्फ जल वाष्प उप–उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। डीजल ट्रेनों की तुलना में ये ट्रेनें टेलपाइप उत्सर्जन को खत्म करती हैं, जीवाश्म ईंधन और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करती हैं और शोर भी काफी कम करती हैं।

संसद सत्र से पहले एनडीए एकजुट, राजनाथ सिंह के आवास पर होगी महत्वपूर्ण बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद का मानसून सत्र अगले सप्ताह से शुरू होगा। ऐसे में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की विधायी कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए अहम बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर एनडीए के नेता जुटेंगे और रणनीति बनाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, संसद के मानसून सत्र से पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए नेताओं की बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि एनडीए नेता आने वाले संसदीय सत्र के लिए गठबंधन की रणनीति बनाएंगे। वहीं, 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। यह बैठक सुबह 9.30 बजे संसद पुस्तकालय भवन के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी। मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 19 जुलाई को सुबह 11 बजे सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। उम्मीद है कि इसमें सरकार अपनी मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में बताएगी, जबकि विपक्ष कई विवादास्पद मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। आगामी सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। संभावनाएं हैं कि विपक्ष नीट पेपर लीक मामले को उठाएगा और श्ऑपरेशन सिंदूरश के दौरान हुई मौतों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों पर सवाल करेगा। कांग्रेस पहले ही रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे चुकी है। इस बार संसद के दोनों सदनों में कई सदस्यों की सीट बदलने की संभावना भी है।

बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर असम, 8,457 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य

असम, (एजेंसी)। असम सरकार ने राज्य के बिजली क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी निवेश योजना की घोषणा की है। इसके तहत 77,353 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर जलविद्युत, सौर, तापीय और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के माध्यम से 8,457 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हिमंत

बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य की वर्तमान 450 मेगावाट उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 8,457 मेगावाट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 77 हजार करोड़ रुपये से अधिक का यह निवेश विकसित असम की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। राज्य का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जयंत मल्लबरुआ ने कहा कि बिजली क्षेत्र में यह अब तक की सबसे बड़ी निवेश योजना है। इसका वित्तपोषण राज्य सरकार के संसाधनों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम को पूर्वोत्तर भारत का हरित ऊर्जा केंद्र और बिजली अधिशेष राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में 4,900 मेगावाट क्षमता वाली चार पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें करीब 27,100 करोड़ रुपये का निजी निवेश होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना परीक्षण चरण में पहुंच चुकी है और फिलहाल लगभग 55 मेगावाट बिजली ग्रिड को उपलब्ध करा रही है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तीन देशों के राजकीय दौरे पर, मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया जाएंगी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 19 से लेकर 25 जुलाई 2026 तक मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया के राजकीय दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मु 20 जुलाई 2026 को मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सैंडू के निमंत्रण पर मोल्दोवा जाएंगी। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का मोल्दोवा का पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान, राष्ट्रपति अपनी समकक्ष माइया सैंडू से मिलेंगी और प्रतिनिधिमंडल के स्तर की बातचीत करेंगी। वह रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मिलेंगी। वह मोल्दोवा–भारत पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के सदस्यों के साथ भी बातचीत के साथ–साथ एक बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगी और भारतीय

समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। भारत और मोल्दोवा के बीच अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। यह दौरा एक अहम और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा और दोनों देशों के संबंधों को एक बड़ी साझेदारी तक ले जाएगा। खेती, स्वास्थ्य सुविधा और फार्मास्यू टिकल्स, आईटी और शिक्षा के क्षेत्रों में आपसी फायदे वाले सहयोग की अच्छी गुंजाइश है। नॉर्थ मैसेडोनिया की प्रेसिडेंट गोरडाना सिलजानोव्स्का– दावकोवा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मु 21–22 जुलाई 2026 तक नॉर्थ मैसेडोनिया भी जाएंगी। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का उत्तरी मैसेडोनिया का पहला दौरा होगा। वह राष्ट्रपति गोर्दाना सिलजानोव्स्का–दावकोवा के साथ द्विपक्षीय बातचीत, प्रधानमंत्री ह्रिस्टिजान मिकोस्की, असेंबली के प्रेसिडेंट से मुलाकात और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को भी संबोधित करेंगी। वह भारत–उत्तरी मैसेडोनिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगी। दोनों पक्षों की कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, विज्ञान और तकनीक, आईटी और आईटीईएस जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को गहरा करने में गहरी दिलचस्पी है। इसके अलावा, रोमानिया के राष्ट्रपति कुसोर डैन के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 23 से 25 जुलाई 2026 तक रोमानिया जाएंगी।

बिम्सटेक भारत के नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट विजन का प्रमुख मंच - अजीत डोभाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने गुरुवार को बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह मंच नेबरहुड फर्स्ट (पड़ोसी पहले) नीति, एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन को दर्शाता है। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, क्षमता निर्माण और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए बिम्सटेक देशों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाना समय की मांग है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डोभाल ने भारत की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ष्भारत के लिए बिम्सटेक नेबरहुड फर्स्ट (पड़ोसी पहले) की हमारी सोच, श्एक्ट ईस्टश नीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और महासागर विजन का प्रतिनिधित्व करता है। यह विजन क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक तथा समग्र प्रगति पर आधारित है।ष उन्होंने कहा, हम ऐसे समय में मिल रहे हैं, जब दुनिया संघर्षों और भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। तेज तकनीकी प्रगति के कारण बहु–आयामी सुरक्षा चुनौतियां और गंभीर हो गई हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (ग्लोबल सप्लाई चेन) में व्यवधान के कारण हमारे सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसे समय में हमारे लिए सहयोग बढ़ाना, आपसी हितों के लिए निर्णायक कदम उठाना और चर्चा व विचार–विमर्श के जरिए साझा चुनौतियों का समाधान निकालना बेहद जरूरी है। डोभाल ने कहा कि बिम्सटेक हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण और गतिशील क्षेत्रों को एक साथ लाता है। उन्होंने कहा, ष्बिम्सटेक के सदस्य देशों की कुल आबादी 1.7 अरब है, जो दुनिया की लगभग 22 प्रतिशत आबादी है। इन देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था करीब 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही साझा सभ्यतागत और सांस्कृतिक विरासत के जरिए भी सदस्य देशों को जोड़ती है। एनएसए ने कहा, इन्हीं ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर बिम्सटेक ने विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत सहयोग विकसित किया है।

भारतीय ब्रांडों, डिजाइनरों और कारीगरों के लिए वैश्विक पहचान बनाने का सुनहरा अवसर – गिरिराज सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारतीय ब्रांडों, डिजाइनरों और कारीगरों के लिए वैश्विक मंच पर अग्रणी पहचान स्थापित करने का यह उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि भारत का वस्त्र एवं परिधान उद्योग पारंपरिक विनिर्माण से आगे बढ़कर डिजाइन नवाचार, गुणवत्ता और सांस्कृतिक विशिष्टता के दम पर वैश्विक पहचान बना रहा है।

भारत टेक्स 2026 के तहत नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विशेष सत्र में उद्योग जगत, डिजाइनरों, ई–कॉमर्स कंपनियों और निर्यातकों ने भारतीय ब्रांडों के वैश्विक विस्तार की रणनीतियों पर विचार–विमर्श किया। सत्र में बताया गया कि वर्ष 2025–26 में भारत का कपड़ा एवं परिधान निर्यात लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बढ़ते नेटवर्क के बीच भारतीय ब्रांडों के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंच, मजबूत ब्रांड पहचान, ओम्नीचौनल रणनीति और बदलती उपभोक्ता जरूरतों के अनुरूप खुद को ढालने पर जोर दिया गया। 'इंडियन ब्रांड्स, ग्लोबल एम्बिशंसरू रीडिफाइनिंग रिटेल ग्रोथ बियॉन्ड बॉर्डर्स' विषय पर आयोजित सत्र में 20 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसमें भारतीय ब्रांडों, लक्जरी डिजाइनरों, ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्मों और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भारतीय वस्त्र एवं लाइफस्टाइल ब्रांडों को वैश्विक बाजार में स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा की। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय कारीगर, डिजाइनर और एमएसएमई देश की समृद्ध शिल्पकला और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की क्षमता रखते हैं।

अग्निवीरों के भविष्य पर धामी का बड़ा भरोसा, सरकार हर कदम पर साथ

देहरादून, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यूथ फाण्डेशन ट्रेनिंग एरिया कुआंवाला, डोईवाला, देहरादून में आयोजित श्अग्निवीर संवादश कार्यक्रम में हजारों युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रसेवा, अग्निवीरों के भविष्य और पुनर्वास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है और सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के तहत प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकारी

सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे राष्ट्रसेवा के बाद उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अग्निवीरों के प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल का प्रभावी उपयोग करते हुए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है, ताकि देश की सेवा करने वाले युवाओं को भविष्य की चिंता न करनी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का युवा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संवेदनशीलता, सम्मान और प्रतिबद्धता के साथ लगातार कार्य कर रही है। साथ ही उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को और सशक्त बनाने तथा युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष ने जंतर–मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जारी प्रदर्शन में जुटे प्रदर्शनकारियों का लगातार पुलिस कैमरे से निगरानी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। वकील सुभाष चंद्रन और अनिरुद्ध केपी के जरिये ये याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस जंतर–मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर स्थायी सर्विलांस कैमरे से लगातार नजर रखी जा रही है। यहां तक कि महिलाओं और लड़कियों के रात में सोने के दौरान भी कैमरे से नजर रखी जा रही है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर कैमरे से लगातार नजर रखने का कोई

कानूनी अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया है कि आइशी घोष 20 जून से लगातार प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। याचिका में कहा गया है कि कैमरे से प्रदर्शनकारियों के खाने और आराम करने के समय का भी वीडियो फिल्माया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कुछ छात्र प्रदर्शनकारियों को यहां तक धमकी दे रहे हैं कि उनका फोटो और वीडियो उनके अभिभावकों और उन संस्थानों को भेज देंगे जहां से वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी वजह से कई लोग प्रदर्शन में हिस्सा लेने से कतरा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों के वीडियो उस हालत में भी बनाए जब भारी बारिश के दौरान वे भींगी हुई थीं और जंतर–मंतर पर छिपने की कोई जगह नहीं थी। ऐसा करना शारीरिक निजता और गरिमा का घोर उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस से बार–बार ये पूछा गया कि लगातार नजर रखने का अधिकार किसने दिया या किस कानूनी प्रावधान से वे ऐसा कर रहे हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। याचिका में निजता के अधिकार पर जस्टिस केएस पुट्टास्वामी के उच्चतम न्यायालय के फैसले का जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा कर दिल्ली पुलिस संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन कर रही है।

संक्षिप्त खबरें

भविष्य के युद्धों की रणनीति पर मंथन, सुदर्शन चक्र कोर की समीक्षा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने सुदर्शन चक्र कोर, शाहबाज डिवीजन और उनसे संबद्ध सैन्य संरचनाओं की ऑपरेशनल तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है। इस दौरान उन्हें युद्धक तत्परता, मिशन की तैयारी और क्षमताओं के विकास से जुड़े विभिन्न प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी गई। समीक्षा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने सुदर्शन चक्र कोर द्वारा संचालित उन्नत सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की पहलों का भी आकलन किया। उन्होंने शाहबाज डिवीजन में स्वदेशी मानव रहित हवाई प्रणालियों (यूएवी) का प्रदर्शन देखा। यहां इस दौरान ड्रोन व यूएवी ने उभरते खतरों के विरुद्ध सटीक लक्ष्य भेदन क्षमता का प्रदर्शन किया। विशेष रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित इन प्रणालियों ने आधुनिक युद्धक्षेत्र में भारतीय सेना की बढ़ती आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता को रेखांकित किया है। सैन्य कमांडर ने इन पहलों की सराहना करते हुए कहा कि यह भारतीय सेना के 'परिवर्तन के दशक' अभियान के अनुरूप स्वदेशी क्षमता निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अपने दौरे में लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने सैनिकों से भी संवाद किया। उन्होंने सभी रैंकों के सैनिकों की पेशेवर दक्षता, परिचालन तैयारी और उत्कृष्टता हासिल करने की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।

नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना भारत निर्वाचन आयोग (म्ब्प्) का अधिकार क्षेत्र नहीं है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (ैप्त्) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग की संवैधानिक भूमिका केवल मतदाता सूची के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अद्यतन तक सीमित है। इसलिए मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हट जाने मात्र से उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त नहीं हो जाती।मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि किसी अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न करने का निर्णय लिया जाता है, तब भी निर्वाचन आयोग स्वयं उसकी नागरिकता पर फैसला नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में नागरिकता से जुड़ा प्रश्न संबंधित मंत्रालय या सक्षम प्राधिकरण के समक्ष भेजा जाना चाहिए, क्योंकि नागरिकता निर्धारण का अधिकार चुनाव आयोग को संविधान या कानून के तहत प्राप्त नहीं है।सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम होना।

संपादकीय

भारत की भूमिका दर्शक भर की

नई दुनिया को परिभाषित करने वाली तकनीकों में अपना प्रतिमान बनाने की होड़ में भारत बहुत पीछे छूट गया है। नतीजतन अमेरिकी या चीनी प्रतिमानों में से किसी एक पर निर्भर होना हमारी नियति बन गई है। खबर है कि फेबल–5 और माइथोस–5 जैसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मॉडल्स तक विदेशियों की पहुंच रोकने के डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन के आदेश के बाद भारत की बड़ी कंपनियां भी चीन के ऑपेन सोर्स मॉडल वाले एआई एजेंट्स की सेवाएं ले रही हैं। सस्ता होने के कारण स्टार्ट–अप कंपनियों के बीच पहले से ही चीनी मॉडल लोकप्रिय हैं। स्पष्टतरू यह रुझान हाई टेक क्षेत्र में हमारी निराशाजनक उपस्थिति का प्रमाण है। नई दुनिया जिन तकनीकों से परिभाषित होगी, उनमें भारत की मौजूदगी महज हेडलाइन और नैरेटिव निर्माण तक सीमित है। जबकि कड़वी हकीकत यह है कि उन तकनीकों में अपना मॉडल और प्रतिमान बनाने के लक्ष्य में भारत बहुत पीछे छूट गया है। ऐसे में अमेरिकी या चीनी प्रतिमानों में से किसी एक पर निर्भर होना हमारी नियति बन गई है। एआई के बाद अब क्वांटम कंप्यूटिंग में अमेरिका और चीन के बीच तीखी होड़ शुरू हो चुकी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्वांटम कंप्यूटिंग को राष्ट्रीय रणनीतिक संपत्ति घोषित करने वाले कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही अमेरिकी कंपनियों के लिए दो बिलियन डॉलर के विशेष पैकेज की घोषणा की। विशेषज्ञों के मुताबिक यह नए तकनीक युद्ध की शुरुआत है। अमेरिका का ध्यान विशेष रूप से क्वांटम वेफर उत्पादन और जीपीएस की जगह लेने वाले क्वांटम सेंसर्स के सैन्य इस्तेमाल पर केंद्रित है, ताकि भविष्य के युद्धों में सिग्नल जैमिंग जैसी चुनौतियों को बेअसर किया जा सके। मगर चीन इस बिसात पर पीछे नहीं है। उसने अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026–2030) में क्वांटम तकनीक को भविष्य के छह प्रमुख उद्योगों में सबसे ऊपर रखा है। मार्केट रिसर्च कंपनी मैकिन्से के अनुमानों के अनुसार चीन का सार्वजनिक निवेश 15 बिलियन डॉलर से अधिक है, जो अमेरिकी सरकारी निवेश से लगभग दोगुना है। जहां अमेरिका निजी क्षेत्र के नवाचार और सेमीकंडक्टर प्रभुत्व पर भरोसा कर रहा है, वहीं चीन का दृष्टिकोण राज्य–नियोजित और रणनीतिक है। इस राह पर चलते हुए उसने इस क्षेत्र में आरंभिक बढ़त बना ली है। यही कथा रॉबोटिक्स और बायोटेक क्षेत्रों की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सब में भारत की भूमिका दर्शक भर की रह गई है।

नेपाल में उठ रही हिंदी की मांग

उमेश

नेपाल की जनकपुर उपमहानगर पालिका ने अपने अधीन प्राथमिक विद्यालय में मैथिली भाषा की पढ़ाई का फैसला लिया है। जनकपुर से महज तीस किलोमीटर दूर भारतीय सीमा में पहले से ही मैथिली की पढ़ाई हो रही है। भारत में मैथिली भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा है। चूंकि जनकपुर के आसपास मैथिलीभाषियों की अच्छी–खासी संख्या है। लिहाजा जनकपुर उपमहानगर पालिका के इस निर्णय का मैथिलभाषी समुदाय में स्वागत होना लाजमी है। लेकिन नेपाल का ही एक वर्ग इस फैसले के विरोध में उतर आया है। दिलचस्प यह है कि उसे मैथिली से कोई बुनियादी विरोध नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि मधेस इलाकों में हिंदी की विधिवत पढ़ाईहोनी चाहिए। हिंदी समर्थक इस वर्ग का तर्क है कि इस कदम से नेपाल में बोली जाने वाली भारतीय मूल की भाषाओं के बीच एकता का संदेश जाएगा और यह एकता मधेस समुदाय की राजनीतिक ताकत को बढ़ावा देगी। लेकिन मधेस समाज के लोग अपनी–अपनी भाषाओं की अगर पढ़ाई पर जोर देने लगेंगे तो इससे मधेस समाज में बिखराव आएगा और उनकी एकता में दरार बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा संख्या के लिहाज से मधेस समुदाय की तुलना में छोटा खस आर्य मूल के नेपाली समुदाय का नेपाल की राजनीति में वर्चस्व बना रह सकता है। नेपाल में भाषा को लेकर उठे इन सवालों पर विचार से पहले मधेस समुदाय के बारे में मोटे तौर पर कुछ बातें समझनाआवश्यक है। नेपाल में पहाड़ी मूल के अलावा तराई में जो लोग रहते हैं, उन्हें मधेस या मधेसी कहा जाता है। मधेस समुदाय की व्यापकता उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल की सीमा तक नेपाली हिस्से में है। नेपाल की कुल जनसंख्या तीन करोड़ है। आंकड़ों के मुताबिक, करीब 53 प्रतिशत यानी लगभग एक करोड़ साठ लाख लोग मधेसी है। नेपाल में बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद यहां की शासन व्यवस्था में पहाड़ी मूल के लोगों का ही वर्चस्व रहा है, जिनकी जनसंख्या करीब एक करोड़ चालीस लाख है। मधेसी समुदाय का अपने सीमावर्ती भारतीय इलाकों के लोगों से रोटी और बेटी का रिश्ता है। वे लोग पहाड़ी मूल के लोगों की बजाय सीमावर्ती भारतीय इलाकों के लोगों की तरह दिखते, रहते, खाते–पीते और बोलते हैं। इनमें अवधी, भोजपुरी, थारू, बज्जिका, अंगिका, मैथिली, सतार, मगही, राजवंशी और मैथिलीभाषी शामिल हैं। नेपाल की राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी के नेता रह चुके रमन पांडेय इन दिनों हिंदी के लिए स्वतंत्र रूप से अभियान चला रहे हैं। उनका तर्क है कि मैथिली की पढ़ाई से उन्हें एतराज नहीं है। लेकिन इससे मधेस समुदाय की आपसी एकता में दरार पड़ेगी। उनका कहना है कि नेपाल का पहाड़ी शासक समुदाय चाहता है कि मधेस समाज की एकता बाधित हो। यह उसके हित में है, क्योंकि मधेस जनसंख्या अगर बंटी होगी तो पहाड़ी मूल के लोगचुनावों में जीतते रहेंगे और कम संख्या के बावजूद वे देश पर शासन करते रहेंगे। नेपाल में 133 भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन यहां मोटे तौर पर नेपाली और अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ाई होती है। नेपाल में हिंदी की पढ़ाई की मांग करने वाले वर्ग का तर्क है कि अगर हिंदी को शासकीय मान्यता मिलती है और उसकी पढ़ाई होती है तो वह नेपाल की सभी 133 भाषाओं के आपसी संपर्क का सबसे बड़ा जरिया होगी। यह मांग कुछ वैसे ही है, जैसे भारत में आपसी संपर्क भाषा के लिए हिंदी को अपनाने का विचार केशवचंद्र सेन, गुजराती कवि नर्मदा शंकर उपाध्याय, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और बिनोबा भावे सदृश हस्तियों ने दिया था। विनोबा और पुरूषोत्तम दास टंडन ने तो देवनागरी लिपि को दूसरी भाषाओं द्वारा अपनाए जाने और उसके विस्तार की जोरदार पैरवी की थी। रमन पांडेय जैसे लोग भी नेपाल में हिंदी को कुछ उसी तरह आगे लाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर हिंदी को मान्यता मिली तो नेपाल की स्थानीय भाषाओं के बीच मजबूत कड़ी बनकर उभरेगी। वैसे भी मधेस समुदाय जब दूसरे भाषा–भाषी से बात करता है तो वह हिंदी का ही सहारा लेता है। इससे नेपाली एकता की भावना को तो मजबूती मिलेगी ही, भारतीय सीमा पार रिश्तों को निभाने में नेपाली लोगों मदद मिलेगी। हिंदी समर्थकों का यह भी तर्क है कि मधेस समुदाय की आपसी एकता को भी हिंदी के ही जरिए मजबूती मिल सकेगी। मधेस आबादी नेपाल के बाइस जिलों में फैली हुई है। रमन पांडेय जैसे लोगों का तर्क है कि बाइस जिलों के लोगों को एक माला में जोड़ने में हिंदी ही कामयाब हो सकती है। रमन पांडेय का कहना है कि नेपाली भाषा बेहद छोटे समुदाय खस आर्य की भाषा है। जिनकी संख्या एक करोड़ भी नहीं है। लेकिन वह पूरे देश की एक मात्र भाषा बनी हुई है। इसमें दो राय नहीं कि नेपाल के तराई यानी मधेस और भारत से सटे इलाकों में हिंदी का प्रभाव गहरा और व्यापक है। नेपाल और भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत साझा है। नेपालमें भी हिंदी का व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है।

परमाणु संयंत्र का डाटा लीक हो गया, ऐसी साइबर सुरक्षा के भरोसे आगे बढ़ेगा डिजिटल इंडिया

नीरज

देश की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़े हजारों गोपनीय दस्तावेज कथित रूप से सार्वजनिक होने के बाद भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना की साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। हम आपको बता दें कि रैनसमवेयर गिरोह च्वर्ल्ड लीक्सष् ने दावा किया है कि उसने संयंत्र से संबंधित 19 हजार से अधिक संवेदनशील फाइलें डार्क वेब पर जारी कर दी हैं। इन दस्तावेजों को लगभग 8 लाख 58 हजार फाइलों के उस बड़े संग्रह का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसे परियोजना से जुड़े ठेकेदार रिलायंस समूह के डाटा से चुराया गया है। हालांकि इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, फिर भी विशेषज्ञ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर मामला मान रहे हैं। इस बीच, रिलायंस समूह ने मीडिया को बताया कि तीसरे पक्ष के भारतीय डाटा सेंटर प्रदाता योट्टा के सर्वर पर रखे गए उसके डाटा में आंशिक सेंधमारी हुई है। कंपनी के अनुसार सरकार को इस घटना की जानकारी दे दी गई है, लेकिन किस प्रकार का डाटा प्रभावित हुआ, इसका खुलासा नहीं किया गया। दूसरी ओर योट्टा ने कहा कि उसने 29 मई को सर्वर पर संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा लिया था और संदिग्ध रैनसमवेयर को सक्रिय होने से रोक दिया गया था। बाद में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने संभावित डाटा लीक के दावे की जानकारी दी। हम आपको बता दें कि कथित रूप से लीक हुए दस्तावेज वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2025 के मध्य तक के बताए जा रहे हैं। इनमें वेंटिलेशन और शीतलन प्रणालियों के इंजीनियरिंग नक्शे, साझा नियंत्रण कक्ष की रूपरेखा, उपकरणों के निरीक्षण प्रतिवेदन, आपूर्तिकर्ताओं की सूची, विक्रेताओं के प्रस्ताव, बैठकों के अभिलेख तथा बीमा संबंधी दस्तावेज शामिल बताए गए हैं। अधिकांश दस्तावेज कुडनकुलम परियोजना की तीसरी और चौथी इकाई से संबंधित हैं, जिनका निर्माण कार्य जारी है और जिनके वर्ष 2027 तक चालू होने की संभावना है। राहत की बात यह है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें परमाणु रिएक्टर के मुख्य तंत्र की रूपरेखा शामिल नहीं है, क्योंकि वह रूस की सरकारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। फिर भी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी जानकारी शत्रुतापूर्ण तत्वों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी हमलावर को यह जानकारी मिल जाए कि परियोजना में किन व्यक्तियों, ठेकेदारों और प्रणालियों की पहुंच कहां तक है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से परमाणु रिएक्टर पर हमला किए बिना भी उससे जुड़ी सहायक व्यवस्थाओं, आपूर्ति श्रृंखला या तीसरे पक्ष की प्रणालियों को निशाना बना सकता है। इससे परियोजना के संचालन, रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था पर अप्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस पूरे मामले की जांच भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। अभी तक इस बात का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि संयंत्र की परिचालन प्रणाली या परमाणु रिएक्टर की सुरक्षा से सीधे समझौता हुआ है। परमाणु ऊर्जा विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। उल्लेखनीय है कि संबंधित हैकर गिरोह पहले भी कई प्रमुख औद्योगिक संस्थानों को निशाना बना चुका है। देखा जाये तो यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक साइबर सुरक्षा कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष भारत में लगभग दो करोड़ नवासी लाख खाते किसी न किसी रूप में डाटा समझौते का शिकार हुए, जिससे भारत विश्व के सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल रहा। वहीं हाल के एक औद्योगिक सर्वेक्षण में पाया गया कि 73 प्रतिशत भारतीय संस्थानों को यह तक जानकारी नहीं थी कि वे कभी साइबर हमले का शिकार हुए हैं या नहीं, जबकि 57 प्रतिशत संस्थानों में बुनियादी साइबर उपायों का भी अभाव है। देखा जाये तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना केवल बिजली उत्पादन का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु क्षमता और सामरिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार भी है। इस परियोजना पर किसी भी प्रकार का साइबर हमला या गोपनीय सूचनाओं का लीक होना सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। आधुनिक युद्ध में साइबर क्षेत्र को भूमि, जल, वायु और अंतरिक्ष के समान ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण अवसंरचना से संबंधित सूचनाओं का दुरुपयोग कर शत्रु देश या संगठित साइबर अपराधी बिना प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई के भी रणनीतिक दबाव बना सकते हैं। बहरहाल, इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल परमाणु संयंत्र की आंतरिक सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि उससे जुडे ठेकेदारों, डाटा सेंटरों, आपूर्ति श्रृंखला और तीसरे पक्ष की डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा भी समान रूप से आवश्यक है। भविष्य में राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा, नियमित सुरक्षा परीक्षण, आपूर्ति श्रृंखला का कड़ा सत्यापन तथा संवेदनशील सूचनाओं की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था विकसित करना अनिवार्य होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी महत्वपूर्ण अवसंरचना की साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाते हुए इस क्षेत्र में निवेश और समन्वय दोनों को और मजबूत करना होगा, ताकि ऐसी घटनाओं से सामरिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रूस-भारत की परमाणु साझेदारी में सेंध कुडनकुलम फिर से सुर्खियों में है

अभिनय

भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम का नाम एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक कथित डाटा ब्रिज जिसने देश के एक बड़े इंफ्रा की साइबर सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल दावा है कि डाक पेप पर करीब 858,000 फाइलें अपलोड की गई हैं। जिसमें से लगभग 19,000 फाइलें कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी बताई जा रही हैं। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट हैक हो गया है या फिर रिएक्टर का डाटा लीक हुआ है या मामला कुछ और है। यह मामला सीधे एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सर्वर से डाटा चोरी का नहीं है। दरअसल कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट थ्री और यूनिट 4 के कुछ इंफ्रा का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट साल 2018 में त्मसपंदबम पदतिं को दिया गया था। इसी कंपनी के डाटा में सेंध लगने का दावा सामने आया है। खुद त्मसपंदबम ने स्वीकार किया कि उसके डाटा में आंशिक यानी कि पार्शियल ब्रीच हुआ है और इसकी जानकारी सरकार को दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्मसपंदबम का डाटा भारतीय डाटा सेंटर कंपनी यो के सर्वर पर होस्ट था। योटा का कहना है कि 29 मई को उसे सर्वर पर संदिग्ध गतिविधियां दिखी थी और संभावित रैंसमवेयर को उसी समय रोक दिया गया था। लेकिन जून के आखिर में त्मसपंदबम ने उसे बताया कि बाहरी हमलावर डाटा चोरी का दावा कर रहे हैं। इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। इस पूरे मामले के पीछे जिस समूह का नाम सामने आया है, उसका नाम वर्ल्ड लीग्स है। यह एक कुख्यात रसमवेयर गिरोह है। इसका तरीका आमतौर पर यह होता है कि पहले किसी कंपनी का डाटा चुराया जाता है। फिरौती मांगी जाती है और अगर पैसे नहीं मिलते तो चोरी किया गया डाटा डाक पर सार्वजनिक कर दिया जाता है। इससे पहले यह गिरोह ज्जं समूह समेत कई बड़ी कंपनियों को निशाना बना चुका है। अब सवाल कि आखिरकार लीक क्या हुआ है? रर्स की रिपोर्ट के मुताबिक डाक वेब पर मौजूद दस्तावेजों में कथित तौर पर यूनिट थ्री और यूनिट फोर से जुड़े वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट सप्लाई की सूची, मीटिंग रिकॉर्ड, जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उपकरणों की समीक्षा और बीमा से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि रॉयर्स ने साफ कहा कि वह इन दस्तावेजों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। एक रैनसमवेयर और जबरन वसूलीकरने वाले समूह वर्ल्ड लीक्स द्वारा कथित तौर पर इस डेटा लीक को अंजाम दिया गया है, जिसने अपने डार्क वेब प्लेटफॉर्म पर चोरी की गई फाइलों का एक बड़ा जखीरा प्रकाशित किया है। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने कहा कि इस समूह ने लगभग 19,000 फाइलों का एक संग्रह जारी किया है, जिसका कुल आकार (डेटा) करीब 14.3 ळठ है। इन फाइलों में केकेएनपीपी भारत के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित खतरे की चिंताओं के बीच, एनपीसीआईएल ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि लीक हुए दस्तावेज रिएक्टर सेफ्टी सिस्टम से जुड़े नहीं थे। कंपनी ने कहा कि यह जानकारी केवल कुडनकुलम यूनिट 3 और 4 के लिए बैलेंस ऑफ प्लांट कॉमन सर्विस सुविधाओं से संबंधित थी, जिनका निर्माण अभी चल रहा है। एनपीसीआईएल ने कहा ये सुविधाएं पारंपरिक किस्म की हैं और आमतौर पर थर्मल पावर प्लांट के साथ–साथ अन्य प्रोसेस इंडस्ट्रीज में भी पाई जाती हैं। इनका न्यूक्लियर सेफ्टी या न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में बाहरी वेंटिलेशन सिस्टम, पानी की आपूर्ति नेटवर्क और अन्य सहायक सेवाएं जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं, जिनके डिजाइन अक्सर बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स के दौरान सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साझा किए जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि रूसी डिजाइन वाले प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर समेत मुख्य रिएक्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर नेटवर्क से अलग रखे गए हैं। ताजा घटना कुडनकुलम प्लांट के सामने आई पहली साइबर सुरक्षा चुनौती नहीं है। 2019 में प्लांट में कजतंबा मैलवेयर के जरिए साइबर घुसपैठ की बात सामने आई थी। साइबर सुरक्षा कंपनियों ने इसे उत्तर कोरिया के सरकारी समर्थन वाले श्लाजरस ग्रुपश से जोड़ा था। यह मैलवेयर प्लांट के लोकल नेटवर्क से जुड़े एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्यूटर पर पाया गया था। जांचकर्ताओं के

अनुसार, यह सिस्टम की जानकारी, की–स्ट्रोक और नेटवर्क की डिटेल्स इकट्ठा करने में सक्षम था। उस समय, छच्ब्स् ने शुरुआत में घुसपैठ की खबरों से इनकार किया था, लेकिन बाद में पुष्टि की कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रभावित हुआ था। कंपनी का कहना था कि रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम अलग–अलग, आइसोलेटेड नेटवर्क से सुरक्षित थे जो इंटरनेट से जुड़े नहीं थे। हाल ही में हुई सुरक्षा चूक ने रिएक्टर कंट्रोल रूम के बाहर साइबर सुरक्षा जोखिमों को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु गतिविधियों के लिए कड़े सुरक्षा उपाय करता है, लेकिन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अक्सर कई प्राइवेट कंपनियां, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शामिल होते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पूरी सप्लाई चेन में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एक जैसे मजबूत नहीं हैं, तो ये बाहरी लिंक कमजोर कड़ी बन सकते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (ब्त्ज्–प्द) और न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि हमलावरों ने कॉन्ट्रैक्टर के सिस्टम तक कैसे पहुँच बनाई और डेटा कैसे निकाला। इस जांच का मकसद सिक्योरिटी में कमियों का पता लगाना और भारत के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े थर्ड–पार्टी नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत करना होगा।

पंजाब के चुनावी प्रचार में राजनीतिक दलों को धार्मिक मुद्दों से बचना चाहिए

डॉ. अरुण

छुट्टियां व मौसमी आयोजन समाज को न तो इतिहास के मुश्किल अध्यायों को मिटाना चाहिए और न ही राजनीतिक फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अतीत का ईमानदारी से अध्ययन किया जाना चाहिए, उस पर तर्कसंगत बहस होनी चाहिए और उसे पूरी तरह से समझा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां वही गलतियां न दोहराएं। जिसे–जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, अक्सर लोगों का ध्यान जरूरी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से हटाने के लिए नए विवाद खड़े किए जाते हैं। बेरोजगारी, कर्ज, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विकास जैसे मुद्दों पर बात करने के बजाय, राजनीतिक चर्चाओं में ऐसे भावनात्मक मुद्दों का बोलबाला बढ़ रहा है जो समाज में बंटवारा बढ़ाते हैं और सत्ता में बैठे लोगों को चुनावी फायदा पहुंचाते हैं।पंजाब ने आपसी टकराव की भारी कीमत चुकाई है। १९८० और १९९० के दशक की शुरुआत में राज्य ने अपने इतिहास के सबसे काले दौर का सामना किया। यहां के लोगों ने शांति बहाल करने और समाज को फिर से खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। हालांकि, राज्य का इतिहास सिर्फ टकराव तक ही सीमित नहीं है। यह साहस, बलिदान और संघर्ष का भी इतिहास रहा है। राजनीति समाचार पत्र आजादी

के बाद भी पंजाबियों ने राष्ट्र–निर्माण में अहम भूमिका निभाई। आकार में छोटा होने के बावजूद, पंजाब भारत का श्अन्न का कटोराश (फूड बाउल) बन गया और देश की खाद्य सुरक्षा में बेमिसाल योगदान दिया।दुर्भाग्य से, १३ अप्रैल १९७९ को अखंड कीर्तनी जत्था, दमदमी टकसाल और निरंकारी समुदाय के बीच टकराव के बाद इतिहास ने एक दुखद मोड़ लिया। इससे अस्थिरता का एक लंबा दौर शुरू हुआ। धीरे–धीरे पंजाब आतंकवाद, अलगाववाद और सरकारी दमन की चपेट में आ गया, जिससे यहां के लोगों को सालों तक हिंसा और डर का सामना करना पड़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, १९८१ और १९९३ के बीच पंजाब में उग्रवाद के कारण २१,३५० लोगों की जानें गईं। इन मुश्किल सालों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कई कार्यकर्ताओं ने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अपनी जानें दीं और श्न हिंदू राज, न खालिस्तानश का नारा लोकप्रिय बनाया, जो सांप्रदायिक बहुसंख्यकवाद और अलगाववाद, दोनों के विरोध को दर्शाता था। इस पूरे दौर में पंजाब के लोगों ने जो जबरदस्त संयम दिखाया, वह भी उतना ही अहम था। पूरे समय के दौरान, और यहां तक कि १९८४ में सिखों के खिलाफ हुए भयानक जनसंहार के बाद भी, पंजाब में कोई जवाबी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जो वहां के सामाजिक ताने–बाने की मजबूती को दिखाता है।जैसे–जैसे उग्रवाद बढ़ा, चरमपंथी समूहों ने ध्ार्मिक स्थलों को अपनी गतिविधियों के ठिकानों के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बिगड़ते हालात का नतीजा जून १९८४ में श्ऑपरेशन ब्लू स्टारश के रूप में सामने आया। इस सैन्य कार्रवाई ने सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई। हालांकि सरकार ने क्षतिग्रस्त अकाल तख्त का पुनर्निर्माण किया था, लेकिन बाद में सिख समुदाय ने इसे खुद फिर से बनवाया। इन घटनाओं के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। श्ऑपरेशन ब्लू स्टारश अपरिहार्य था या कोई और तरीका अपनाया जा सकता था, यह आज भी बहस का विषय है। जिस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, वह यह है कि उस समय पंजाब डर के साये में था। उग्रवादियों ने कर्फ्यू लगा दिए, रोजमर्रा की जिंदगी को नियंत्रित करने वाले फरमान जारी किए, लोगों को स्वतंत्रता दिवस न मनाने का निर्देश दिया और यहां तक कि ड्रेस कोड भी लागू किए, खासकर महिलाओं के लिए। समुदाय या धर्म से परे, लोगों के मन में डर और अविश्वास की गहरी भावना थी।जब उग्रवाद फिर से बढ़ा, तो १९८६ में अकाली सरकार के तहत श्ऑपरेशन ब्लैक थंडरश शुरू किया गया, जिसके बाद १९८८ में एक लंबा ऑपरेशन चला, जिसमें श्री हरमंदिर साहिब परिसर से उग्रवादियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के उलट, ऑपरेशन ब्लैक थंडर को काफी ज्यादा पारदर्शिता के साथ चलाया गया और नतीजतन, इससे जनता में बहुत कम नाराजगी पैदा हुई। अलगाववादी आंदोलन के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान और केनडा व यूनाइटेड किंगडम में मौजूद कट्टरपंथी समूहों से आर्थिक और राजनीतिक समर्थन मिला। एक्जिक्यूटिव ब्रांच इस दौरान केंद्र सरकार के हालात से निपटने के तरीकों में बड़ी कमियां और राज्य की एजेंसियों द्वारा गलत कामों के मामले भी सामने आए। जहां हजारों पुलिसकर्मियों ने आतंकवाद के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, वहीं गैर–कानूनी हत्याओं, लोगों के जबरन गायब किए जाने, गैर–कानूनी वसूली और सत्ता के दुरुपयोग के कई मामले भी सामने आए। इन उल्लंघनों ने लोगों का भरोसा कम किया और नाराजगी बढ़ाई। साथ ही, आतंकवादी समूहों ने आम नागरिकों पर क्रूर हमले किए, जिससे वे लोग उनसे दूर हो गए जिनका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे। जैसे–जैसे लोगों का समर्थन कम होता गया, आतंकवाद धीरे–धीरे कमजोर होता गया और १९९३ तक काफी हद तक खत्म हो गया। लंबे समय तक चले इस संघर्ष ने पंजाब की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया। डर, अनिश्चितता और अविश्वास के कारण लोगों ने पलायन किया, निवेश कम हुआ, उद्योग कमजोर हुए और आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ गई। इसके सामाजिक नतीजे दशकों बाद भी महसूस किए जा रहे हैं। इसलिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन दर्दनाक घटनाओं से एक बार फिर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इस संदर्भ में, केंद्र सरकार का पहले श्सतलुजश फिल्म को मंजूरी देना और फिर उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने का फैसला गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसा लगता है कि यह सुलह को बढ़ावा देने के बजाय सांप्रदायिक बंटवारा पैदा करने के मकसद से किया गया था। विडंबना यह है कि श्सतलुजश को दबाने की कोशिश ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी, जिससे पंजाब भर में कई लोगों ने इसे अनौपचारिक तरीकों से देखा। राजनीति समाचार पत्र समाज को न तो इतिहास के मुश्किल अध्यायों को मिटाना चाहिए और न ही राजनीतिक फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अतीत का ईमानदारी से अध्ययन किया जाना चाहिए, उस पर तर्कसंगत बहस होनी चाहिए और उसे पूरी तरह से समझा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां वही गलतियां न दोहराएं। उदाहरण के लिए, जर्मनी एडॉल्फ हिटलर का महिमामंडन नहीं करता, फिर भी वहां कसंट्रेशन कैंपों को स्मारकों के रूप में संरक्षित रखा गया है जो आने वाली पीढ़ियों को फासीवाद के खतरों के बारे में शिक्षित करते हैं। आज पंजाब तीन दशक पहले की तुलना में कहीं अधिक शांतिपूर्ण है। फिर भी नई चुनौतियां सामने आई हैं। संगठित अपराध, नशीली दवाओं की तस्करी, जबरन वसूली और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों की संलिप्तता वाली फिरौती की बड़ी मांगों की खबरें स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। पंजाब ने नफरत और विभाजन की भारी कीमत पहले ही चुकाई है। समय की मांग यह है कि चुनावी लाभ के लिए पुराने घावों को फिर से न खोला जाए, बल्कि सामाजिक सद्भाव को मजबूत किया जाए। सार्वजनिक बहस को उन मुद्दों, जिनसे सामाजिक शांति भंग होने और आपसी विश्वास व सह–अस्तित्व के बंधन कमजोर होने का खतरा हो, के बजाय इन जरूरी चुनौतियों पर केंद्रित किया जाना चाहिए।

लखनऊ में 17 वर्षीय घरेलू सहायिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के सआदतगंज थाना क्षेत्र के रामनगर सी–ब्लॉक स्थित एक मकान में 17 वर्षीय घरेलू सहायिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवती का शव मकान के बाथरूम में फंदे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार मकान स्वामी ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने के बजाय युवती को फंदे से उतारकर बरामदे में लिटा दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है।पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई 2026 की रात लगभग 9 बजे थाना सआदतगंज क्षेत्र के रामनगर सी–ब्लॉक स्थित एक मकान में एक युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना सआदतगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।जांच में मृतका की पहचान रजनी (17 वर्ष), पुत्री रामशरण, निवासी ग्राम सुल्तानपुर, थाना सदरपुर, जनपद सीतापुर के रूप में हुई। वह अविवाहित थी और पिछले लगभग तीन वर्षों से रामनगर स्थित मकान में घरेलू कार्य, जैसे झाड़ू–पोछा आदि, करती थी।प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना के समय युवती ने मकान के बाथरूम में फांसी लगा ली थी। पुलिस के अनुसार मकान स्वामी रामगोपाल वर्मा ने पुलिस को तत्काल सूचना दिए बिना पहले युवती को फंदे से उतारकर मकान के बरामदे में लिटा दिया। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रामगोपाल वर्मा की मोहन रोड स्थित फतेहगंज चौराहे पर एक आभूषण की दुकान भी है।घटना की सूचना मिलते ही फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया।

इटावा के पूर्व विधायक राम लखन धोबी के पुत्र ऋषि दिवाकर समर्थकों संग कांग्रेस में शामिल

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में इटावा के लखना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय राम लखन धोबी के पुत्र ऋषि दिवाकर ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा।इस अवसर पर अजय राय ने ऋषि दिवाकर और उनके समर्थकों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगातार लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, जिससे संगठन को मजबूती मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भगवान राम के नाम पर राजनीति कर सत्ता हासिल की, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े मामलों में चंदा, जमीन खरीद और चढ़ावे को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है ।

बीबीएयू में यूजी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के स्नातक (यूजी) एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सीयूईटी–यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद पात्र अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध यूजी प्रवेश प्रॉस्पेक्टस 2026–27 तथा छात्रावास (हॉस्टल) मैनुअल का सावधानीपूर्वक अध्ययन अवश्य करें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।विश्वविद्यालय के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी 5 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इस अवधि में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 1000 रुपये का अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा।पंजीकरण शुल्क अनारक्षित (यूआर), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये निर्धारित किया गया है।प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

नाबालिग से दुर्व्यवहार के आरोप में युवक गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। लिस कमिश्नरेट लखनऊ के अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पीजीआई थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका से कथित दुर्व्यवहार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है।पुलिस के अनुसार, एसजीपीजीआई चरण भट्टा रोड क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना पीजीआई में मुकदमा संख्या 374ध्2026 धारा 74, 352 बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 9(एम)ध्10 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले शनि भारती ने नाबालिग बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार किया।मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चरण भट्टा रोड क्षेत्र से आरोपी शनि भारती (26 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से मोहनलालगंज क्षेत्र का निवासी है और वर्तमान में पंचम खेड़ा, चरण भट्टा रोड पर रह रहा था।पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पड़ोस में रहने वाली बच्ची को अपने साथ खेलने के लिए छत पर ले गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है।पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसबीआई एटीएम तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गुडम्बा पुलिस ने एसबीआई एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखी नकदी चोरी करने का प्रयास करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध 12 बोर तमंचा, दो जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त पेचकस, प्लास और आरी ब्लेड बरामद किए गए हैं।पुलिस के अनुसार, 12 जुलाई 2026 को राम धर्म कांटा के पास स्थित एसबीआई एटीएम में अज्ञात व्यक्ति ने मशीन को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखी धनराशि चोरी करने का प्रयास किया था। घटना के संबंध में गुडम्बा थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।

श्रेया जायसवाल ने नीट में हासिल की शानदार सफलता, क्षेत्र में खुशी का माहौल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। मडियाहूं नगर के व्यवसायी सतीश जायसवाल की पुत्री एवं पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी सोनी जायसवाल की भतीजी श्रेया जायसवाल ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। श्रेया की सफलता की खबर मिलते ही परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने इसे उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया। श्रेया ने अपनी लगन और निरंतर

प्रयासों से यह सिद्ध कर दिया कि लक्ष्य के प्रति समर्पण और मेहनत से हर सफलता हासिल की जा सकती है। इस उपलब्धि पर परिजनों ने एक–दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी का इजहार किया। वहीं क्षेत्र के गणमान्य लोगों और शुभचिंतकों ने श्रेया को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सभी ने विश्वास जताया कि वह चिकित्सा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर समाज की सेवा करेंगी। श्रेया की इस सफलता से मड़ियाहूं क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल है। उनकी उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। परिवार ने श्रेया की सफलता का श्रेय उनकी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता–पिता के सहयोग को दिया।

संत रविदास अमृत भारत एक्सप्रेस का जौनपुर सिटी स्टेशन पर होगा भव्य स्वागत

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। संत रविदास की तपोस्थली छेराहटा (अमृतसर) से उनकी जन्मस्थली वाराणसी तक संचालित संत रविदास अमृत भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या14623/14624) का शुभारंभ आज 17 जुलाई को अमृतसर से किया गया। यह नई एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार, 18 जुलाई को प्रातः 11:00 बजे जौनपुर जनपद के जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी, जहां संत रविदास के अनुयायियों द्वारा इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर रेल मंत्रालय की पहल के तहत इस बार किसी जनप्रतिनिधि अथवा राजनीतिक दल के नेताओं के स्थान पर संत रविदास पंथ के अनुयायियों द्वारा ही ट्रेन के स्वागत का निर्णय लिया गया है। इसे सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जौनपुर सिटी स्टेशन पर स्वागत कार्यक्रम का नेतृत्व रमेश बौद्ध जी एवं रमेश चंद्र गौतम जी करेंगे। दोनों वरिष्ठ समाजसेवी अपने रविदासिया समुदाय के साथ शनिवार, 18 जुलाई को प्रातः 11:00 बजे स्टेशन पर उपस्थित रहकर संत रविदास अमृत भारत एक्सप्रेस का स्वागत करेंगे। रेलवे प्रशासन की तरफ से स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार उपाध्याय तथा वाणिज्य विभाग की ओर से आरक्षण पर्यवेक्षक अनुराग तिवारी को सौंपी गई है। रेलवे अधिकारियों द्वारा यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं स्वागत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया हैं। संत रविदास अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन संत रविदास के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह उनकी तपोस्थली अमृतसर और जन्मस्थली वाराणसी को सीधे रेल मार्ग से जोड़ती है। इस नई रेल सेवा से श्रद्धालुओं एवं आम यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष हाउस अरेस्ट, दूल्हे को श्रद्धांजलि देने जा रहे थेपुलिस ने आवास को छावनी में बदला, अन्य नेता भी नजरबंद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । जनपद के बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड के पीड़ित आजाद बिंद को श्रद्धांजलि देने जा रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह को पुलिस ने उनके सुजानगंज स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया। इसी क्रम में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान को भी जौनपुर शहर स्थित उनके आवास पर नजरबंद किया गया। उनके घर पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के साथ पार्टी के जिला सचिव इरशाद खान, रमेश बेबी और कांग्रेस नेता फिरोज खान को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था

चरमरा गई है और हत्याओं का सिलसिला जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है और हत्या तथा बलात्कार की घटनाओं से प्रदेश में भय का माहौल है। डॉ. सिंह ने भाजपा सरकार पर संविधान और लोकतंत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रही है, जबकि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी दिवंगत व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना इस प्रदेश में अपराध बन गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा की ष्डबल इंजनष् सरकार से ऊब चुकी है। डॉ. सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार की बुलडोजर नीति ष्राम मंदिर के चंदा चोरों, हत्यारों, बलात्कारियों और अपराधियोंष् का संरक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को सत्ता से हटा देगी।

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डॉ. मोनिका सिंह बनीं कार्यवाहक निदेशक

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए डॉ. मोनिका सिंह को कार्यवाहक निदेशक, उच्च शिक्षा नियुक्त किया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग–5 की ओर से गुरुवार को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। जारी आदेश के अनुसार, शासन ने 31 दिसंबर 2025 को जारी उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत डॉ. बिंद्रावन लाल शर्मा, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा को कार्यवाहक निदेशक का दायित्व सौंपा गया था। शासन ने अब कार्यहित में डॉ. मोनिका सिंह, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोएडा (गौतमबुद्धनगर) को अग्रिम आदेशों तक कार्यवाहक निदेशक, उच्च शिक्षा के पद पर तैनात किया है। शासन ने डॉ. मोनिका सिंह को तत्काल प्रभाव से निदेशक, उच्च शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अतिरिक्त दायित्व के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि यह निर्णय सक्षम स्तर की स्वीकृति के बाद लिया गया है। आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों तथा प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों समेत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेजी गई है।

पासपोर्ट की तारीख आगे, हज आवेदन की घड़ी पीछे सत्यापन में देरी से सैकड़ों इच्छुकों की चिंता बढ़ी

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में हज 2027 पर जाने का सपना संजोए कई लोग इस बार पासपोर्ट सत्यापन में देरी के कारण आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं। जून में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले अनेक आवेदकों को अभिलेख सत्यापन की तिथि छह अगस्त या उसके बाद की मिली है, जबकि हज आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। ऐसे लोगों का कहना है कि यदि शासन हज आवेदन की अंतिम

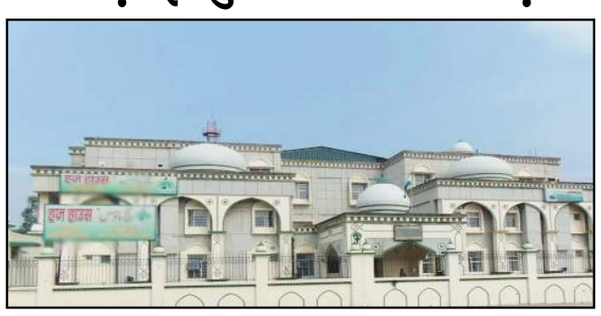

तिथि नहीं बढ़ाता या पासपोर्ट सत्यापन के लिए विशेष व्यवस्था नहीं करता, तो वे इस वर्ष हज की सआदत हासिल करने से वंचित रह जाएंगे। हज आवेदन प्रक्रिया 22 जून से शुरू हुई थी ।

एसकेडी न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों की नीट –2026 में शानदार सफलता

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ एसकेडी न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर नीट 2026 में उत्कृष्ट परिणाम देकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्थान के 107 से अधिक विद्यार्थियों का चयन नीट –2026 में हुआ है। संस्थान के जिन विद्यार्थियों ने विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनमें फाज अहमद ने ऑल इंडिया रैंक 713 (कैटेगरी रैंक 434), आदित्य विक्रम सिंह ने AIR 3422 (कैटेगरी रैंक 1671), आकृति श्रीवास्तव ने AIR 4032 (कैटेगरी रैंक 388), अमृत हर्षल खीवासरा ने AIR 10036 (कैटेगरी रैंक 1100), मंदावी श्रीवास्तव ने AIR 13187 (कैटेगरी रैंक 5255) तथा आर्यन शुक्ला ने AIR 15192 (कैटेगरी रैंक 5941) प्राप्त कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों

के चयन की जानकारी भी लगातार प्राप्त हो रही है। संस्थान के संस्थापक प्रो. श्री एस.के.डी. सिंह एवं निदेशक श्री मनीष सिंह ने सभी चयनित विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। चयनित विद्यार्थियों के सम्मान में अगस्त 2026 में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी चयनित विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार एवं आकर्षक उपहार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। सभी चयनित विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, अपने माता–पिता, आदरणीय प्रो. श्री एस.के.डी. सिंह तथा संस्थान के समस्त शिक्षकों को दिया, जिनके मार्गदर्शन, समर्पण एवं नवीन शिक्षण तकनीकों ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हिंदू-मुस्लिम नहीं, युवाओं के मुद्दों पर होगा यूपी चुनाव-मौलाना डॉ. कल्बे रुशेद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में विश्व विख्यात इस्लामी विद्वान मौलाना डॉ. कल्बे रुशेद रिजवी ने कहा कि सभी धर्म मानवता और आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। नगर के बाजार भुआ स्थित स्वर्गीय मीर बहादुर अली इमामबाड़े में मजलिस–ए–अलम नौचंदी को संबोधित करने के बाद गुरुवार रात देश की उपासना ब्यूरो प्रमुख से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज आदम थे और हम सभी उनकी संतान हैं। सनातन धर्म हो या इस्लाम, हर व्यक्ति को अपने ईश्वर, अल्लाह, गॉड या भगवान की अपने तरीके से उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता है। पीओके के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। उनका कहना था कि वहां की जनता पाकिस्तान की सेना के अत्याचार झेल रही है और आने वाले समय में पीओके के लोग भी भारत के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ईरान के हालात पर बोलते हुए मौलाना ने कहा कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने चार दशकों तक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान पर हुए हमलों और

अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर दुनिया की चुप्पी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता ने कर्बला से अन्याय के खिलाफ संघर्ष का संदेश सीखा है। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से उठाई गई मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि पेपर लीक जैसे मुद्दों से परेशान युवाओं के हित में जल्द समाधान निकलना चाहिए। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और वक्फ बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर उन्होंने कहा कि दोनों ही घटनाएं लोगों की आस्था से जुड़ी हैं। सरकार को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मौलाना ने कहा कि अब केवल हिंदू–मुस्लिम की राजनीति प्रभावी नहीं होगी। देश और प्रदेश का युवा रोजगार, शिक्षा और भविष्य के मुद्दों पर मतदान करेगा। हालांकि राजनीतिक दल जातीय समीकरणों के आधार पर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन आने वाला चुनाव नई राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को कानून के दायरे में विवाह करने का अधिकार देता है। किसी की निजी जिंदगी को अनावश्यक रूप से विवाद का विषय बनाना उचित नहीं है। उन्होंने अंत में कहा कि भारत की प्रगति के लिए सभी धर्मों और समाजों को मिलकर काम करना होगा।

आयुष्मान योजना में बड़ा खेल, एक ही परिवार के सदस्यों को बार–बार भर्ती कर निकाले लाखों, ऐसे खुली पोल

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अस्पतालों की बड़े पैमाने पर मनमानी सामने आई है। एक ही परिवार के सदस्यों को बार–बार भर्ती करके योजना के रुपये खर्च किए गए। इसी तरह जरूरत न होने पर भी मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया है। यह खुलासा साचीज की ओर कराए गए औचक निरीक्षण में हुआ है। आयुष्मान भारत के तहत पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए साचीज लगातार सख्त निगरानी कर रही है। इसी के तहत विभिन्न जिलों में जांच शुरू कराई गई है। कई स्थानों पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के पालन में कमी और गुणवत्ता संबंधी खामियां सामने आईं। निरीक्षण में सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। साचीज की

सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि तीन सदस्यीय विशेष टीम ने बिजनौर जिले के 20 विभिन्न सूचीबद्ध अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इनमें से 16 अस्पतालों में दिशानिर्देशों का पालन नहीं पाया गया। इनमें से 6 अस्पतालों को निलंबन नोटिस के साथ भुगतान रोकने का आदेश दिया गया जबकि 10 अस्पतालों को अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन अस्पतालों में लापरवाही मिलेगी और जुर्माना नहीं दिया है। वहां जुर्माने की गणना नए सिरे से की जाएगी और 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। ऑडिट एजेंसी को भी नोटिस जारी किया गया है और जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी इस मामले में कारण बताओ नोटिस दिया गया है। सीईओ ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े प्रत्येक सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए योजना के सभी दिशानिर्देशों, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन और गुणवत्ता मानकों का शत–प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य है।

लखनऊ पुलिस ने हाईटेक फ्यूल चोरी और मिलावट करने वाले संगठित गिरोह का किया भंडाफोड़

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 'ऑपरेशन इथेनॉल शील्ड' के तहत पेट्रोल–डीजल की चोरी, अवैध मिलावट और कालाबाजारी में संलिप्त एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, अपमिश्रित ईंधन, साल्वेंट तथा चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह आधुनिक तकनीक, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, हाई सिक्योरिटी लॉकिंग सिस्टम और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दुरुपयोग कर सुनियोजित तरीके से ईंधन चोरी और मिलावट का कारोबार संचालित कर रहा था।पुलिस के अनुसार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक दावों की जांच के दौरान यह संदेह हुआ कि वाहनों में आने वाली तकनीकी समस्याओं के पीछे पेट्रोल और डीजल में अवैध मिलावट तथा ईंधन चोरी का नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। इसी के बाद क्राइम ब्रांच ने विशेष अभियान 'ऑपरेशन इथेनॉल शील्ड' शुरू किया।विश्वसनीय सूचना पर थाना मलिहाबाद क्षेत्र के सन्यासी बाग फ्लाईओवर के पास छापेमारी की गई, जहां एक फ्यूल टैंकर और अन्य वाहन से 7,750 लीटर पेट्रोल, 4,000 लीटर डीजल, लगभग 1,150 लीटर अपमिश्रित पेट्रोल, 3,200 लीटर साल्वेंट तथा चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए। आबकारी विभाग की संयुक्त जांच में ईंधन की चोरी और मिलावट की पुष्टि हुई।

मिल्कीपुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गौमाता को संवैधानिक दर्जा देने की उठाई मांग

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।शुक्रवार को ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी गौमाता जनजागरण यात्रा के तहत मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे।यात्रा के दौरान अमानीगंज से लेकर मिल्कीपुर बाजार और विभिन्न चौराहों पर श्रद्धालुओं, गौभक्तों तथा समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दोपहर करीब एक बजे शंकराचार्य सांसद अवधेश प्रसाद के पांच नंबर स्थित आवास पहुंचे, जहां आयोजित पादुका पूजन कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया।इस अवसर पर सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी, अजीत प्रसाद और अमित प्रसाद ने परिवार सहित शंकराचार्य की पादुकाओं का विधिवत पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौमाता को पशु की श्रेणी से हटाकर ष्माताष का संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार स्वयं को गौभक्त और हिंदू हितैषी बताती है तो उसे गाय को माता घोषित करने का साहस भी दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर वे देशभर में जनजागरण अभियान चला रहे हैं।कहा कि शंकराचार्य ने ष्दीमकों की कहानीष का उल्लेख करते हुए वर्तमान व्यवस्था पर तीखा कटाक्ष किया।उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दीमकों में कुछ ही दीमक पूरे समूह को संचालित करते हैं और अधिकांश केवल अपना पेट भरने में लगे रहते हैं,उसी प्रकार आज की व्यवस्था भी दीमकग्रस्त हो चुकी है।हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या सरकार का नाम नहीं लिया।इस मौके पर शंकराचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोष में चोरी होने के बावजूद जिम्मेदारी तय नहीं की गई और गिरफ्तार किए गए लोगों को केवल ष्बलि का बकराष बनाया गया।उन्होंने यह भी दावा किया कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, लेकिन चंपत राय के इस्तीफे को लेकर केवल प्रचार किया गया,वास्तविक इस्तीफा नहीं हुआ।इस अवसर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ सेवा एवं जनजागरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लवलेश पांडे और अखिलेश पांडे को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, मिल्कीपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजीत प्रसाद, अमित प्रसाद, राघवेंद्र प्रताप सिंह श्अनूपश, पृथ्वीराज यादव, विकास सिंह (छोटू), रामजी पाल, सोनू तिवारी, महेश शर्मा, वेद प्रकाश यादव, संतोष यादव, पंकज शुक्ला, महेंद्र यादव, राम लहु यादव, राम बहादुर यादव, रमेश रावत,विकास यादव सहित बड़ी संख्या में गौभक्त, सनातन धर्मावलंबी, समाजवादी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नवागत एसडीएम मिल्कीपुर पवन कुमार शर्मा ने संभाला कार्यभार

अयोध्या। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील में प्रशासनिक फेरबदल के तहत एसडीएम सुधीर कुमार का तबादला कर दिया गया है।उनके स्थान पर अब पवन कुमार शर्मा ने मिल्कीपुर के नए उपजिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।इस बड़े बदलाव के बाद से ही पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है और स्थानीय जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक कई गंभीर सवाल तैरने लगे हैं।क्षेत्र में उठ रहे हैं तीखे सवाल नवनियुक्त एसडीएम के पदभार ग्रहण करते ही क्षेत्र की जनता और प्रबुद्ध वर्ग यह उम्मीद लगाए बैठा है कि क्या अब तहसील की कार्यप्रणाली में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा।क्षेत्र में इस समय निम्नलिखित मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है।तहसील परिसर में भ्रष्टाचार और श्प्राइवेटश कमीरू तहसील परिसर में फैले कथित भ्रष्टाचार और फाइलों के रखरखाव व सरकारी कामकाज में दखल देने वाले अनाधिकृत (प्राइवेट) कर्मचारियों पर क्या नए एसडीएम नकेल कस पाएंगे।क्या इन शबिचौलियोंश के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगेगी?अवैध मिट्टी खनन और पर्यावरण को चोट क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे अवैध मिट्टी खनन और हरे–भरे प्रतिबंधित पेड़ों के अवैध कटान पर क्या प्रशासन अब सख्ती दिखाएगा,या फिर पहले की तरह ही यह खेल पर्दे के पीछे चलता रहेगा जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल इस पूरे घटनाक्रम और क्षेत्र की बदहाल कानून व प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी और भूमिका पर भी जनता लगातार सवाल खड़े कर रहे है।नवागत एसडीएम पवन कुमार शर्मा के लिए मिल्कीपुर तहसील की छवि को सुधारना और बुनियादी जनसमस्याओं का पारदर्शी निस्तारण करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।

एक उप निरीक्षक सहित दो पुलिसकर्मी निलंबित

अयोध्या।एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर एक उपनिरीक्षक तथा एक आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।एसएसपी डा0 गौरव ग्रोवर ने थाना कैन्ट पर तैनात उप निरीक्षक रणजीत सिंह को विवेचनात्मक कार्यवाही के प्रति लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।इसके अलावा उन्होंने थाना कोतवाली अयोध्या पर नियुक्त आरक्षी अंकित पाण्डेय को 10.06.2026 से अनवरत गैरहाजिर रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है,जिनके विरुद्ध विभागीय जांच आसन्न है।

शतचंडी महायज्ञ के लिए निकाली कलश यात्रा

भदोही, (संवाददाता)। क्षेत्र पंचायत कार्यालय परिसर स्थित दुर्गा मंदिर से कलश यात्रा निकालकर सात दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा में पारंपरिक परिधानों में महिलाओं और पुरुषों के साथ ही बच्चे भी उत्साह से शामिल हुए। दुर्गा मंदिर से निकली कलश यात्रा विकास खंड, तहसील, गांधी चौक से बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर घाट पहुंची। जहां श्रद्धालुओं ने कलश में गंगाजल भरा। इसके बाद सिर पर कलश लेकर इसी मार्ग से होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। यज्ञ संयोजक उमाशंकर द्विवेदी और पंकज मिश्रा ने बताया कि काशी के धर्माचार्य सात दिन तक शतचंडी पाठ भजन–कीर्तन, हवन–पूजन करेंगे। इसके अलावा शाम के समय शिव पुराण कथा सुनाई जाएगी।

45 लाख से 350 मीटर अंडरग्राउंड नाली व सीसी रोड का होगा काम

भदोही, (संवाददाता)। नगर में जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर करने के साथ–साथ सड़कों की हालत सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है। नगर पंचायत 15वें वित्त की धनराशि से दो वार्ड को जोड़ने वाली 350 मीटर सीसी रोड व अंडरग्राउंड नाला का निर्माण कराएगी। करीब 45 लाख की लागत से वार्ड नंबर दो शहीद नगर से वार्ड नंबर आठ शिवाजी नगर तक नाली व सीसी रोड का काम धनराशि आवंटन के बाद शुरू होगा।नई बाजार नगर पंचायत में कुल 11 वार्ड हैं। नगर के कई वार्ड में जलनिकासी और इंटरलाकिंग की समस्या है। खासकर वार्ड तीन, चार, दो, सात और नौ जैसे वार्डों में गंभीर समस्या देखने को मिलती है। नगर की आबादी करीब 20 से 25 हजार के आसपास है। बोर्ड की बैठकों में मिले प्रस्तावों के आधार पर नगर पंचायत में कार्य कराया जाता है। वार्ड दो से वार्ड आठ के बीच क्षतिग्रस्त नाली व इंटरलॉकिंग को लेकर काफी समय से समस्या चली आ रही थी। जिसको लेकर मिली शिकायत के बाद बीते दिनों प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। नगर में वार्ड नंबर दो शहीद नगर से वार्ड नंबर आठ शिवाजी नगर तक नाली व सीसी रोड का काम 15वें वित्त की धनराशि से कराया जाएगा।

वसूली में उदासीनता पर तहसीलदार ज्ञानपुर को उपभोक्ता आयोग की नोटिस

भदोही, (संवाददाता)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बुधवार को तहसीलदार, सदर, ज्ञानपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पटेलनगर, ज्ञानपुर स्थित ग्लोबल मोटर शोरूम के डीलर के खिलाफ जारी वसूली आदेश में उदासीनता बरते जाने पर आयोग ने नोटिस जारी कर 22 जुलाई तक स्पष्टीकरण मांगा है। जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि जलालपुर, पनवरिया निवासी राम सजीवन यादव ने डीलर ग्लोबल मोटर (शोरूम) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि उन्होंने डीलर से एक ई–रिक्शा पंजाब एंड सिंध बैंक से फाइनेंस कराकर खरीदा था। जिसमें उसने सभी कागज एक माह अंदर देने का आश्वासन दिया था, लेकिन नहीं दिया। जिससे उसके वाहन का पंजीयन नहीं हो सका।

सीडीओ ने संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर अधिकारियों व कर्मियों को दिये आवश्यक निर्देश

अयोध्या। संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किशोरों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सराहनीय पहल की जा रही है।हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर के किशोरों की पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से नियमित शिक्षण व्यवस्था शुरू की गई है,ताकि वे भविष्य में शिक्षित,आत्मनिर्भर एवं जिम्मेदार नागरिक बन सकें।गुरुवार को सीडीओ केके सिंह ने संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण कर शिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया।इस मौके पर उन्होंने किशोरों से संवाद कर उनकी शैक्षिक प्रगति की जानकारी ली तथा अधिकारियों को शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो उन्हें नई दिशा देकर समाज का सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बना सकती है।बताते चले कि उन्हे शिक्षा के प्रति जागरुक करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से 4 विभिन्न विषयों के अध्यापकों को उन किशोरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लगाया गया है।इस संबंध में डीपीओ जयपाल वर्मा ने बताया कि वहां पर निरुद्ध किशोरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 6 अध्यापकों डीआईओएस के माध्यम से तथा 4 अध्यापकों को बीएसए के माध्यम से जा रहे है।जेल अधीक्षक रन बहादुर वर्मा ने बताया कि अभी वर्तमान समय में 4 शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग से नियमित आ रहे हैं।वही इंटर तक के किशोरों को पढाने के लिए अच्छा अध्यापक के लिए मांग की गई है।सीडीओ के निरीक्षण के दौरान एडीआईओएस अवनीश कुमार पांडेय,जेलर रन बहादुर वर्मा, डीपीओ जयपाल वर्मा, प्रधानाचार्य जीआईसी ओंकारनाथ के अलावा शिक्षकों में अरुण प्रकाश सिंह वेद प्रकाश आनंद पाठक हितेश शर्मा शाहिद अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

नेपाल में सक्रिय था नकली मुद्रा गिरोह, भारत-नेपाल दोनों जगह के 6 लोग गिरफ्तार

गोरखपुर, (संवाददाता)। नेपाल पुलिस ने रूपनदेही के बुटवल उपमहानगर पालिका–छह स्थित नेपालगंज रोड पर एक दुकान पर छापा मारकर नकली नेपाली मुद्रा छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में एक भारतीय नागरिक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6.22 लाख नेपाली रुपये के नकली नोट और नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गंगा कुमारी पूर्वछाने (36) निवासी बुटवल–11, किरण कृष्ण तिवारी उर्फ कृष्णा निवासी पोखरा–एक (कास्की), संजय थारू निवासी बाणगंगा–एक (कपिलवस्तु), रामचंद्र खत्री (41) निवासी चंगुनारायण–एक (भक्तपुर), पासंग तमांग (38) निवासी शैलुंग–4 (दोलखा) और भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित भक्तिनगर थाना क्षेत्र निवासी वसुमित्र आनंद (49) के रूप में हुई है। बुटवल एरिया पुलिस कार्यालय डीएसपी निशांत श्रीवास्तव ने बताया कि नेपालगंज रोड स्थित एक दुकान पर छापेमारी के दौरान नकली नोट छापने में प्रयुक्त कलर प्रिंटिंग मशीन बरामद की गई। इसके अलावा घर और कमरों की तलाशी में 1,000 नेपाली रुपये के 622 नकली नोट मिले। इनकी कुल कीमत 6.22 लाख नेपाली रुपये है। मौके से एक फोटोकॉपी मशीन, डेल लैपटॉप, प्रिंटर, नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाला विशेष कागज, लैमिनेशन मशीन, विभिन्न रसायन, प्लास्टिक शीट, नकली नोट काटने की मशीन तथा छह मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध करेंसी संबंधी अपराध के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरोह के नेटवर्क और इसके अन्य संभावित सदस्यों की भूमिका की जांच की जा रही है।

'जिलाधिकारी ने लाभार्थी को आपदा राहत राशि का किया चेक वितरित'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' शुक्रवार को जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट में आपदा राहत मद से स्वीकृत धनराशि का चेक लाभार्थी को प्रदान किया तहसील तिलहर के ग्राम सैदापुर निवासी स्वर्गीय कुसुमा देवी पत्नी रामदास की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके विधिक वारिस रामदास पुत्र ज्वाला प्रसाद को दैवीय आपदा राहत मद से ध्4,00,000 की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी। किन्तु बैंक खाते के आईएफएससी कोड में त्रुटि के कारण धनराशि लाभार्थी के खाते में प्राप्त न होकर बैंक ऑफ बड़ौदा, गुजरात शाखा में स्थानांतरित हो गई थी। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर धनराशि को वापस प्राप्त कराया गया तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शाहजहांपुर के माध्यम से लाभार्थी को चेक के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसी क्रम में आज मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार की उपस्थिति में श रामदास को ध्4,00,000 की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर संबंधित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में भी आयुष्मान कार्ड से इलाज की तैयारी

गोरखपुर, (संवाददाता)। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में भी जल्द ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उपचार की सुविधा शुरू होने जा रही है। अभी तक यह सुविधा केवल मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में उपलब्ध है, जहां आयुष्मान लाभार्थियों के लिए विशेष काउंटर संचालित किया जाता है। यहां पंजीकरण के बाद मरीजों के कैशलेस इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में आयुष्मान योजना लागू होने से हृदय, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी समेत गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक ऐसे मरीजों को उपचार के लिए अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र लाभार्थी सीधे सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में योजना का लाभ लेकर इलाज करा सकेंगे। मेडिकल कॉलेज प्रशासन इसके लिए आवश्यक तैयारियों में जुटा है। योजना के संचालन के लिए यहां भी आयुष्मान सहायता काउंटर स्थापित किया जाएगा, जहां मरीजों के गोल्डन कार्ड का सत्यापन और इलाज से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सकेगी। प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में आयुष्मान भारत योजना लागू होने से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को उच्चस्तरीय इलाज आसानी से उपलब्ध होगा। साथ ही उन्हें इलाज के लिए अनावश्यक भागदौड़ और अतिरिक्त खर्च से भी राहत मिलेगी। जल्द ही यह व्यवस्था शुरू की जाएगी।

गोपीगंज शहर से नहीं जाएंगे वाहन

वाराणसी, (संवाददाता)। नगर में निकलने वाले जगन्नाथ रथयात्रा को लेकर गोपीगंज कस्बे में प्रशासन की ओर से व्यापक यातायात डायवर्जन प्लान किया गया है। यातायात प्रभारी राकेश सिंह के अनुसार यह व्यवस्था शाम चार बजे से यात्रा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। जिसमें भारी और छोटे वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि गोपीगंज कस्बे में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। विभिन्न मार्गों से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्तों पर मोड़ा जाएगा। कठौता कट से गोपीगंज की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। गिराईध दानूपुर मार्ग से भी गोपीगंज में प्रवेश बंद रहेगा। ज्ञानपुर जाने वाले वाहन दानूपुर–नथईपुर मार्ग से भेजे जाएंगे। गोपपुर चौराहा पर छोटे वाहनों को रैपुरी गांव होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा। भारी वाहनों को इसी चौराहे पर रोका जाएगा।

अभियान खत्म, स्कूली वाहनों में बच्चों को ठूंसकर ढोने का सिलसिला शुरू

भदोही, (संवाददाता)। स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से दो सप्ताह से चल रहा मिशन सेफ फ्यूचर समाप्त हो गया लेकिन सड़क पर हालात अब भी जस के तस हैं। शहर और कस्बों की सड़कों पर क्षमता से अधिक बच्चों को ठूंसकर स्कूली ऑटो और ई–रिक्शा आते–जाते दिखे। जिस मार्ग से अधिकारियों आते–जाते है उस मार्ग पर भी ऐसे वाहन दिखे। एक से 15 जुलाई तक चले अभियान के पहले सप्ताह में परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधकों और वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक किया। दूसरे सप्ताह में प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस दौरान 37 स्कूली वाहन सीज, 57 वाहनों का चालान किया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 28.20 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया।

महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम पर एयरपोर्ट निदेशक ने यात्रियों से लिया फीडबैक

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। हवाई जहाज से रामनगरी आने–जाने वाले यात्री कैसा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं।इसकी जानकारी के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,पर एयरपोर्ट के निदेशक धीरेंद्र सिंह ने स्वयं टर्मिनल भवन में यात्रियों से संवाद किया।इस मौके उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया।एयरपोर्ट निदेशक ने यात्रियों से सुरक्षा जांच व्यवस्था,स्वच्छता, प्रतीक्षालय, चेक–इन प्रक्रिया, सूचना एवं मार्गदर्शन, कर्मचारियों के व्यवहार तथा अन्य यात्री सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की।इस मौके पर उन्होंने यात्रियों से पूछा कि उन्हें एयरपोर्ट की सेवाएं कैसी लगीं तथा भविष्य में किन क्षेत्रों में और सुधार किया जा सकता है। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर उपलब्ध स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं यात्री–अनुकूल वातावरण की सराहना करते हुए कर्मचारियों के सहयोगपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा की।साथ ही कुछ यात्रियों ने हवाई सेवाओं के विस्तार,उड़ानों की संख्या बढ़ाने तथा विभिन्न गंतव्यों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी संबंधी सुझाव भी दिए।इस अवसर पर एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि यात्रियों की राय एवं सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।प्रत्येक उपयोगी सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा सेवाओं में निरंतर सुधार करते हुए यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुखद यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम यात्रियों की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने तथा ग्राहक संतुष्टि के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में एयरपोर्ट ने ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय स्थान भी प्राप्त किया है।

बोर्ड बैठक में कार्यकारिणी के छह पदों के लिए होगा चुनाव

गोरखपुर, (संवाददाता)। नगर निगम के मेयर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव की अनुमति से नगर निगम (बोर्ड) सदन की 20 वीं बैठक में शोक प्रस्ताव पारित कर दो मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद बैठक स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को बोर्ड की पुनरू बैठक होगी। इसमें कार्यकारिणी के छह पदों पर चुनाव होगा। नगर निगम के सदन हाल में सभी पार्षदों की मौजूदगी में मेयर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव ने शोक प्रस्ताव लाते हुए बताया कि जटेपुर वार्ड में चार बार सपा से पार्षद रहे पूर्व पार्षद श्रवण यादव का आठ जुलाई को निधन हो गया है। बैठक में दिवंगत आत्मा के लिए दो मिनट का मौन धारण करते हुए श्रद्धांजलि दी गयी। इसके बाद मेयर के आदेश पर सदन की बैठक को स्थगित कर दी गई। उन्होंने कहा कि बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11:00 बजे से होगी। इसमें कार्यकारिणी सदस्यों व उपसभापति का चुनाव होगा इसके बाद मतगणना भी शाम को होगी। इस अवसर पर अपर नगर अतुल कुमार, अपर नगर आयुक्त गौरव रंजन श्रीवास्तव, सहायक नगर आयुक्त रवि कुमार सिंह के साथ तमाम पार्षद गण मौजूद रहे। कार्यकारिणी से उपसभापति समेत ये सदस्य होंगे बाहर रू नगर निगम की कार्यकारणी में मेयर डॉ मंगलेश, उप सभापति पवन कुमार त्रिपाठी, श्रवण पटेल, ऋषि मोहन वर्मा, रमेश यादव, छोटेलाल गुप्ता, सरोज पासवान, जिलाउल इस्लाम, अशोक कुमार मिश्र, रामगति निषाद, पूनम सिंह, मीरा यादव और रंजुला यादव शामिल हैं। कार्यकाल पूरा होने के चलते भाजपा पार्षद उपसभापति पवन त्रिपाठी, ऋषि मोहन वर्मा, छोटे लाल यादव, श्रवण पटेल एवं सरोज पासवान और समाजवादी पार्टी से पार्षद रमेश यादव कार्यकारिणी से बाहर होंगे।

रेलवे स्टेशन की दुकान पर छापा-मिलावट की आशंका

गोरखपुर, (संवाददाता)। अगर आप बाहर की बिरयानी खाने के शौकीन हैं तो अब सतर्क हो जाइए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित एक बिरयानी दुकान पर छापा मारकर बिरयानी का नमूना जांच के लिए लिया। निरीक्षण के दौरान बिरयानी में हानिकारक कृत्रिम रंग मिलाए जाने की आशंका जताई गई। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण समाप्त हो चुका था, इसके बाद भी कारोबार संचालित किया जा रहा था। विभाग को मिली शिकायत के आधार पर टीम ने औचक निरीक्षण किया। मौके पर रखी बिरयानी के रंग और गुणवत्ता पर संदेह होने पर उसका नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. सुधीर सिंह ने कहा कि प्रयोगशाला है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।